

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 077/2019 (रि.वि.) (GCMS 2019/00275)	दायर दिनांक 28.11.2019	निर्णय दिनांक 20.10.2021
---	---------------------------	-----------------------------

## अनवान

मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय मकराना-रोड, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर मुख्यालय-17, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर (राज.) तथा आर. के. नगर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रार्थी

बनाम

1. चेतना पत्नि दिनेशचन्द, जाति टांक उम्र वयस्क निवासी बस स्टैण्ड के पास, माहेश्वरी बीज भण्डार के सामने, निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक शाखा निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अमित नाहर  
संजय आगाल  
केएल सुखवाल

अधिवक्ता प्रार्थी  
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1  
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

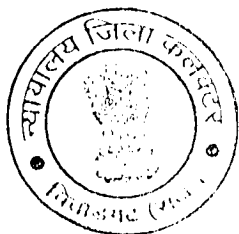
-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में सीमेंट प्लांट लगाने के लिये राज्य सरकार के खान विभाग ने प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत लाइम स्टोन (सीमेण्ट-ग्रेड) की आपूर्ति हेतु ग्राम फलवा, भटकोटडी, रसूलपुरा, लसडावन, माल्याखेडी एवं पीरखेडा की 740.930 हैक्टेयर भूमि के लिये खनन-पट्टा संख्या 22/07 अनुदान किया है जिसकी लीज-डीड प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में दिनांक 08.09.2008 को निष्पादित होकर उप पंजीयक निम्बाहेडा दिनांक 11.09.2008 को पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी इस खनन क्षेत्र में अवाप्त की गई भूमि पर खनन कार्य कर रही है एवं करेगी। प्रार्थी कम्पनी के उक्त



(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

खनन क्षेत्र में विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम भटकोटडी तहसील निम्बाहेडा में खाता नम्बर 61 खसरा नम्बर 210मी0 क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर कृषि भूमि में विपक्षी का दर्ज सम्पूर्ण हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी कम्पनी के राज्य सरकार से स्वीकृत माईनिंग लीज ग्राम फलवा के समीप विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम भटकोटडी के खसरा नम्बर 210मी0 क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बंजड। भूमि में विपक्षी का सम्पूर्ण हक एवं हिस्सा निहित होकर स्थित है। जिसकी प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग के आनुषंगिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी एवं नवशा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि कम्पनी को अपनी माईनिंग लीज क्षेत्र में खनन-प्रयोजनार्थ एवं अन्य प्रयोजनार्थ (Subsidiary purposes) आवागमन हेतु सडक निर्माण एवं श्रमिकों के आवास गृहों के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि की आवश्यकता है। उक्त कृषि भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी को सीमेण्ट उत्पादन हेतु रोड के अभाव में आवश्यक कच्चा माल (लाईम स्टोन) फैक्ट्री में उपलब्ध नहीं हो सकेगा तथा श्रमिकों के आवास गृह के अभाव में कम्पनी द्वारा सीमेण्ट उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि के अलावा खनन प्रयोजनार्थ आवागमन एवं अन्य आनुषंगिक कार्यों हेतु माईनिंग लीज क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(2) एवं (4) के अन्तर्गत खनन के प्रयोजनार्थ अवाप्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी कम्पनी को सीमेण्ट उत्पादन के लिये आवश्यक खनन-कार्यों के आनुषंगिक प्रयोजनार्थ (Subsidiary purposes) प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि की आवश्यकता होने से प्रार्थी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(2) एवं (4) के अनुसार विपक्षी की कृषि भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण कराने का अधिकारी है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अर्वाइ के अनुसार प्रार्थी कम्पनी विपक्षी को कृषि भूमि की मुआवजा राशि अदा करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थी कम्पनी को प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि के खनन-कार्यों के आनुषंगिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। उक्त कृषि भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी के सीमेंट प्लान्ट हेतु कच्चा माल लाने एवं ले जाने के कार्य पर विपरित प्रभाव होगा। अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर विपक्षीगण अन्यत्र कृषि भूमि प्राप्त कर सकेंगे। विपक्षी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के अन्तर्गत अवाप्त किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है सो स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम भटकोटडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित विपक्षी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 210 मी0 क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अर्वाइ पारित फरमाया जावें। विपक्षी को मुआवजा राशि का भुगतान कर भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावें तथा राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि को माईनिंग लीज(खनन) के अन्य आनुषंगिक प्रयोजनार्थ वण्डर सीमेंट लिमिटेड के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।



५  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया एवं उप पंजीयक निम्बाहेडा से उक्त ग्राम की सिंचित/असिंचित कृषि भूमि की सडक के पास अथवा दूर आबादी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से आराजीयात जैरबहस के संबंध में आबादी से दूरी की स्थिति, भूमि में स्थित संरचना, निर्माण, वृक्ष, पत्थर कोट आदि की मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट के निर्देश दिये गये।

दिनांक 24.12.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता महेन्द्र पोखरना हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता केएल सुखवाल हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/पंजीयन/2019/367 दिनांक 09.12.2019 से ग्राम भटकोटडी तहसील निम्बाहेडा की कृषि भूमि की वर्तमान प्रचलित बाजार दर प्रति हैक्टेयर प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2019/972 दिनांक 19.12.2019 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 06.12.2019 प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 21.01.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 08.09.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 05.10.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली हेतु निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी कम्पनी वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में सीमेंट प्लान्ट लगाने के लिये राज्य सरकार के खान विभाग ने प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत लाइम स्टोन (सीमेण्ट-ग्रेड) की आपूर्ति हेतु ग्राम फलवा, भटकोटडी, रसूलपुरा, लसडावन, माल्याखेडी एवं पीरखेडा की 740.930 हैक्टेयर भूमि के लिये खनन-पट्टा संख्या 22/07 अनुदान किया है जिसकी लीज-डीड प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में दिनांक 08.09.2008 को निष्पादित होकर उप पंजीयक निम्बाहेडा दिनांक 11.09.2008 को पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी के उक्त खनन क्षेत्र में विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम भटकोटडी तहसील निम्बाहेडा में खाता नम्बर 61 खसरा नम्बर 210मी0 क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर कृषि भूमि में विपक्षी का दर्ज सम्पूर्ण हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी कम्पनी के राज्य सरकार से स्वीकृत माईनिंग लीज ग्राम फलवा के समीप विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम भटकोटडी के खसरा नम्बर 210मी0 क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बंजड1 भूमि में विपक्षी का सम्पूर्ण हक एवं हिस्सा निहित होकर स्थित है। जिसकी प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग के आनुषंगिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि कम्पनी को अपनी माईनिंग लीज क्षेत्र में खनन-प्रयोजनार्थ एवं अन्य प्रयोजनार्थ



३  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

(Subsidiary purposes) आवागमन हेतु सडक निर्माण एवं श्रमिकों के आवास गृहों के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि की आवश्यकता है। उक्त कृषि भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उत्पादन हेतु रोड के अभाव में आवश्यक कच्चा माल (लाईम स्टोन) फैक्ट्री में उपलब्ध नहीं हो सकेगा तथा श्रमिकों के आवास गृह के अभाव में कम्पनी द्वारा सीमेंट उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि के अलावा खनन प्रयोजनार्थ आवागमन एवं अन्य आनुषंगिक कार्यों हेतु माईनिंग लीज क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(2) एवं (4) के अन्तर्गत खनन के प्रयोजनार्थ अवाप्त किया जाना न्यायोचित है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी कम्पनी में माननीय न्यायालय को भ्रमित करने के लिये अस्पष्ट व आधारहीन कथन किये हैं। प्रार्थी कम्पनी को आवागमन हेतु सडक निर्माण एवं श्रमिकों के आवास गृहों के निर्माण हेतु विपक्षीया की खातेदारी की भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि के अलावा खनन प्रयोजनार्थ आवागमन एवं आनुषंगिक कार्यों के लिए माईनिंग लीज क्षेत्र वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है जहाँ तक विपक्षीया की खातेदारी कब्जेयाबी की ग्राम भटकोटडी के खसरा नम्बर 210 मी० क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बजड। भूमि को माईनिंग आनुषंगिक प्रयोजनार्थ के लिए प्रार्थी कम्पनी के हित में अवाप्त किये जाना आवश्यक होने का प्रश्न है इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि विपक्षीया की उक्त भूमि किस्म बंजड नहीं है बल्कि सिंचित भूमि है जिस पर विपक्षीया रबी व खरीफ की दोनों फसलों की बुवाई कर काश्त करती चली आ रही है। विपक्षीया एवं उसके परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन यही कृषि भूमि है अन्य कोई कृषि भूमि विपक्षीया के नाम पर नहीं है परंतु प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त कृषि भूमि को अपने स्वार्थ व निजी फायदे के लिये अवाप्त की जा रही है जिससे विपक्षीया की खातेदारी की कृषि भूमि कृषि उपयोग के नहीं रहेगी इस प्रकार प्रार्थी कम्पनी भूमि को बर्बाद करना चाहती है जो उचित नहीं है। विपक्षीया की उक्त कृषि भूमि पर विपक्षीया के द्वारा खेतीबाडी का कार्य किया जाता है इससे सालाना करीब एक लाख रुपये आमदनी प्राप्त हो जाती है जिससे विपक्षीया का अपना तथा अपने परिवार का जीवन का जैसे-तैसे गुजर बसर हो जाता है। विपक्षीया के पास आय का अन्य स्रोत नहीं है। इस कारण प्रार्थी को उक्त आराजी भूमि की नैसर्गिक एवं सद्भावी आवश्यकता है। विपक्षीया के परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन यह भूमि ही होने व काफी मेहनत से उक्त भूमि को सिंचित करने से विपक्षीया की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि वर्तमान में विपक्षीया के लिए काफी बेशकियती जमीन है जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। विपक्षीया के अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है। इसलिये इस कृषि भूमि का मूल्यांकन रुपये से किया जाना संभव नहीं है। परंतु फिर भी भूमि को माईनिंग आनुषंगिक प्रयोजनार्थ के लिये प्रार्थी कम्पनी के हित में अवाप्त किया जाना आवश्यकत है तो इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा विपक्षीया के पडौसियों को 35 लाख रुपये प्रति बीघा भूमि मुआवजा राशि देकर कृषि भूमियाँ क्रय की गई



८३  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

इस कारण यदि यदि प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उत्पादन के लिये विपक्षीया की कृषि भूमि की आवश्यकता राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के अनुसार है तो विपक्षीया उक्त कृषि भूमि की प्रति बीघा 35 लाख रुपये की राशि बतौर मुआवजा प्राप्त करना चाहती है तथा उक्त मुआवजा राशि प्रार्थी कम्पनी के द्वारा अदा किये जाने के पश्चात् ही विपक्षीया की उक्त कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उत्पादन के लिये आवश्यक खनन कार्यों के लिये सबसेडीडेयरी परपज के लिये अवाप्त कर भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दी जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी बैंक के यहा भारग्रस्त एवं रहन कर विपक्षी संख्या 1 ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सुविधा ले रखी है। इस ऋण की अदायगी का भार इन आराजीयात पर होने से विपक्षी संख्या 1 के जिम्मे की बकाया ऋण राशि की अदायगी होने पर ही यह आराजीयात भारमुक्त हो पायेगी। इसलिये प्रकरण में निर्धारित किये जाने वाली मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी बैंक को किया जाना आवश्यक है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उत्पादन के लिये आवश्यक खनन-कार्यों के आनुषंगिक प्रयोजनार्थ (Subsidiary purposes) प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि की आवश्यकता होने से प्रार्थी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के अनुसार विपक्षी की कृषि भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण कराने का अधिकारी है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी कम्पनी विपक्षी को कृषि भूमि की मुआवजा राशि अदा करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थी कम्पनी को प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि के खनन-कार्यों के आनुषंगिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। उक्त कृषि भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी के सीमेंट प्लान्ट हेतु कच्चा माल लाने एवं ले जाने के कार्य पर विपरित प्रभाव होगा। अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर विपक्षीगण अन्यत्र कृषि भूमि प्राप्त कर सकेंगे। विपक्षी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के अन्तर्गत अवाप्त किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है सो स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम भटकोटडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित विपक्षी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 210 मी० क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अवार्ड पारित फरमाया जावे। विपक्षी को मुआवजा राशि का भुगतान कर भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि को माईनिंग लीज(खनन) के अन्य आनुषंगिक प्रयोजनार्थ वण्डर सीमेंट लिमिटेड के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक



८ ३  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

परिशीलन किया। सुनी गई बहस के तथ्यों पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली को निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों का अवलोकन किया।

**89 Right of minerals, mines, quarries and fisheries –**

- 1 The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall, have all powers necessary for the enjoyment of such a right.
- 2 The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.
- 3 If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions and reservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned: Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered.
- 4 If, in the exercise of the right herein referred over any land, the rights of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the State Government or its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, or, if this award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).
- 5 No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.
- 6 If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub-section (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as if it were an arrear of land revenue.
- 7 Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in and has not been assigned by the State Government, shall without prejudice to any other section that may be taken against his liable, on the order in writing of the Collector to pay a



५  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़

penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:

Provided that if the sum so calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding one thousand rupees as the Collector may impose.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय पाया है। अधिनियम की धारा 89 (2) के अनुसार सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और उत्खनन के उद्देश्य के लिए भूमि तक पहुंच का अधिकार और कार्यालयों, कामगारों के आवास और मशीनरी के निर्माण सहित अन्य सहायक भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है। खनिजों को जमा करना और कचरा जमा करना, सड़कों, रेलवे या ट्राम लाइनों का निर्माण, और कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार खनन और उत्खनन के लिए सहायक घोषित कर सकती है। इसके साथ अधिनियम की धारा 89 (4) अनुसार किसी भी भूमि पर निर्दिष्ट अधिकार के प्रयोग में, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ऐसी भूमि की सतह के कब्जे या गड़बड़ी से होता है, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिनी ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के उल्लंघन के लिए मुआवजे का भुगतान करेगा और ऐसे मुआवजे की राशि की गणना कलक्टर द्वारा की जाएगी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षीगण की कृषि भूमि जो प्रार्थी कम्पनी की स्वीकृत माईनिंग लीज व प्लान्ट के समीप स्थित होने से आनुषांगिक कार्य हेतु कन्वेयर बेल्ट हेतु विपक्षीगण की भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही अप्रार्थीगण की ओर से पत्रावली पर इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा खनन कार्य में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज एरिया में स्थित होकर कम्पनी को उक्त भूमि की खनन प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ लिये जाने के संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात आराजी संख्या खसरा नम्बर 210मी0 क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर कृषि भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संरचना विवरण	कीमत संरचना(रुपये में)
1.	.....	0/-
	संरचनाओं का कुल योग	0/-

हमने उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत की गई इस ग्राम की सिंचित/असिंचित/बीड़ भूमि की आबादी एवं सड़क से पास



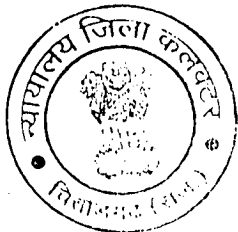
२५  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

तथा दूर की जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों का अवलोकन किया। उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की दर 12,48,210/-रूपये प्रति हैक्टेयर होना बताया है, किन्तु हम भूमि का खनन प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लिये जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दरों की दुगुनी दर 24,96,420/-रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि का मुआवजा निर्धारित करना उचित मानते हैं।

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	मुआवजा हेतु निर्धारित दर प्रति हैक्टेयर (रूपये में)	देय राशि (रूपये में)
भटकोटडी	210मी0	0.51	2496420	1273175/-
कुल किला - 1		कुल क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर	कीमत संरचना	0/-
			योग	1273175/-
			100 % सोलिशियम	1273175/-
			कुल देय राशि	2546350/-
अक्षरे पच्चीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र/-				

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त तालिका अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि का खनन एवं आनुषांगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही भूमि वर्तमान में रहन दर्ज रिकार्ड है, जिससे आराजीयात को भारमुक्त कराया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु दो पृथक्-पृथक् बैंक संबंधित बैंक एवं खातेदार के नाम, तहसीलदार निम्बाहेडा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन एवं आनुषांगिक कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेन्ट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम माईनिंग लीज के अन्य आनुषांगिक प्रयोजनार्थ प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीजडीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन के आनुषांगिक कार्य हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को नियमानुसार पालना बाबत भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



र  
(संकरा चन्द्र मीठीपा)  
जिला कलेक्टर,  
जयपुर